भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5431

जिसका उत्तर 25 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

04 चैत्र, 1948 (शक)

बक्सर और कैमूर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

5431. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार राज्य में विशेषकर बक्सर और कैमूर जिलों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों, भूमि की उपलब्धता और इनकी आवश्यक अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बक्सर और कैमूर जिलों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलेक्ट्रॉनिक हब स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, स्थल की पहचान करने या नीतिगत अनुमोदन के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) क्या अब तक किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) यदि नहीं, तो उक्त जिलों में रोजगार सृजन, स्टार्टअप और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार भविष्य में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** भारत सरकार छोटे शहरों और कस्बों सहित पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस पहल के एक भाग के रूप में, टियर-II/टियर-III शहरों में 62 केंद्रों सहित पूरे भारत में 70 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र स्थापित किए गए हैं।

<u>बिहार में एसटीपीआई केंद्र:</u>

सरकार ने बिहार में भागलपुर, दरभंगा और पटना में कुल 273 प्लग एंड प्ले सीटों के साथ 3 एसटीपीआई केंद्र स्थापित किए हैं। ये एसटीपीआई केंद्र इनक्यूबेशन सेवाएं, हाई स्पीड डेटा संचार सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और अन्य वैधानिक सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि नवीन विचारों वाले उद्यमी एसटीपीआई की मदद से अपने स्टार्टअप स्थापित कर सकें।

इन्क्यूबेशन सुविधा वेंचर कैपिटलिस्टों (वीसी), आईआईटी/एनआईटी/उद्योग के सलाहकारों और आईटी पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग के अवसर जैसे निवेशकों के साथ बैठक करने का अवसर प्रदान करती है।

वर्तमान में, एसटीपीआई के पास बिहार राज्य में नए एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

अब तक, बिहार में एसटीपीआई केंद्रों में इनक्यूबेट की गई 12 आईटी/आईटीईएस कंपनियों ने लगभग 366 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन योजना (एनजीआईएस) के तहत समर्थित पटना के 31 स्टार्टअप ने लगभग 253 रोजगार के अवसर सृजित किए है।

आईआईटी पटना में इनक्यूबेशन सेंटर जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स (जेनेसिस) योजना के तहत स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पांच वर्षों की अवधि में बिहार राज्य में 310 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आईआईटी पटना और बिहार सरकार के सहयोग से इन्क्यूबेशन सेंटर (चरण-II) की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है।

सरकार बिहार सहित देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई पहलें शुरू कर रही है। इनमें नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), डिजीलॉकर और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और कार्यान्वयन शामिल है, साथ ही एमईआईटीवाई-सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सरकारी विभागों को सुरक्षित क्लाउड सेवाओं का प्रावधान भी शामिल है।

इसके अलावा, नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी को सक्षम करने संबंधी पहलों में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार-आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवा वितरण का विस्तार शामिल है।

*****